छत्तीसगढ़ की द्वितीय विधान सभा
अष्टम सत्र

लेफ्टि.जन. के.एम. सेठ

पी.वी.एस.एम., ए.वी.एस.एम.(से.नि.)

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 13 फरवरी, 2006

माननीय सदस्यगण,

नए वर्ष 2006 में आयोजित विधान सभा के इस प्रथम अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। मैं आप सभी को राज्य गठन और विधान सभा के पांच वर्ष पूरे होने की भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विगत पांच वर्षों में राज्य ने अनेक क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाओं की पहचान की है। विकास की अनेक मंजिलें तय की हैं। सुखद भविष्य के लिए मजबूत आधार बनाया है।

2. मेरी सरकार ने उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ध्यान देने की रणनीति अपनाई जिन क्षेत्रों के लोग ज्यादा समस्याओं और अभावों से जूझ रहे थे। इनमें प्रमुख रूप से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्र हैं जिनसे ग्रामवासी अत्याधिक प्रभावित होते हैं, साथ ही बिजली, पानी, सड़क एवं सिंचाई जैसे क्षेत्र भी हैं जो प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की बुनियादी आवश्यकता है।

इन क्षेत्रों में मेरी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार मैं आगे करूंगा किन्तु प्रारम्भ में ही मैं यह बताना चाहता हूं कि इन क्षेत्रों में उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं। उदाहरण के रूप में किसानों को 9 प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी ऋण, 12 हजार नलकूपों का खनन, 53 करोड़ की लागत से हार्टीकल्चर मिशन लागू करना, 35 लाख टन धान का उपार्जन करना तथा एक लाख पम्पों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना शामिल है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 874 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना, स्वास्थ्य अधोसंरचना की कमी को दूर करने के लिए यूरोपियन कमीशन के साथ 150 करोड़ रू. की साझेदारी का कार्यक्रम तथा 64 एफ.आर.यू. के माध्यम से 24 घण्टे स्वास्थ्य एवं सुरक्षित प्रसव की सेवा उपलब्ध कराना है। शिक्षा के क्षेत्र में 31 हजार शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति, एक हजार नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 1800 नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 29 लाख बच्चों को प्रतिदिन गर्म मध्यान्ह भोजन तथा 45 लाख निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शामिल है।

3. बिजली के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार विद्युत आपूर्ति के लिए अटल ज्योति योजना तथा बिजली के पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन पर 1014 करोड़ रू. का निवेश शामिल है। नए बिजली घरों की स्थापना में मुख्य रूप से विद्युत मण्डल द्वारा 500 मेगावाट का कोरबा पूर्व एवं 500 से 600 मेगावाट क्षमता के कोरबा पश्चिम की स्थापना के साथ–साथ इफको के सहयोग से 1000 मेगावाट का विद्युत गृह सरगुजा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। सिंचाई के क्षेत्र में 137 योजनाओं को पूर्ण कर एक लाख 73 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया। 37 एनीकट निर्मित किए जा चुके हैं तथा 59 एनीकट निर्माणाधीन हैं। पेयजल आपूर्ति के लिए नई 11 हजार 803 बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा, जबकि ग्रामीण जल प्रदाय की 839 योजना पूर्ण कर ली गई है। आगामी तीन वर्षों में 10 लाख शौचालय के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता का एक नया अध्याय शुरू होगा। सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। 3 हजार 661 किलोमीटर सड़कों, 38 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। नाबार्ड से मिले ऋण से

441 करोड़ रू. की लागत से 144 सड़कों तथा 220 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है, साथ ही ए.डी.बी. से 1246 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त की गई है जिससे पूरे प्रदेश में उच्च स्तर की सड़कों का निर्माण पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 800 करोड़ रू. की लागत से 4 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कों एवं 6 हजार पुल–पुलियों का निर्माण किया जा चुका है।

4. अब मैं मेरी सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से विवरण रखना चाहता हूं। मेरी सरकार द्वारा सुनिश्चित सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के लिए नई पहल करते हुए किसान समृद्धि योजना, लघु सिंचाई (नलकूप) योजना एवं शाकम्बरी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसमें नलकूप खनन, नवीन कूप निर्माण तथा पम्प प्रतिस्थापन के लिए किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में लगभग 12 हजार नलकूपों का खनन किया गया। 45 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की गई है। आगामी 3 वर्षों में लगभग 40 हजार नलकूप तथा कूप खनन किया जाएगा।

5. उच्च गुणवत्ता एवं प्रमाणित बीजों के प्रदेश में उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष जोर दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु, सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर आधार एवं प्रमाणित बीज का वितरण करने का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत किसानों को वर्ष 2005–2006 में लगभग 40 लाख रू. के बीज वितरित किए गए हैं। गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु कारखाना क्षेत्र में गन्ने की खरीदी पर 10 रू. प्रति क्विंटल का बोनस भी स्वीकृत किया गया है।

6. मेरी सरकार ने किसानों को उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न संस्थाओं का विकास जरूरी समझा। राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की गई। विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों में स्थानीय कृषकों की भागीदारी बढ़ाने हेतु 5 जिलों कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा एवं जगदलपुर में समन्वित प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। समन्वित कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला बिलासपुर में स्थापित की जा रही है।

7. मेरी सरकार द्वारा खेती को लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न नगद फसलों, दलहन–तिलहन और उद्यानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नेशनल हार्टीकल्चर मिशन योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत केन्द्र से 53 करोड़ रू. की कार्ययोजना स्वीकृत कराई गई है। 10,000 हेक्टेयर रकबे में फल, मसाला, औषधि एवं सुगंधित फसलों तथा पुष्प विकास के कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। उद्यानिकी फसलों के रखरखाव, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट की स्थापना हेतु भी आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान है।

8. मेरी सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उसके सुखद परिणाम भी मिलने शुरू हुए हैं। देश में न्यूनतम 9 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने

से किसानों की सुविधा में वृद्धि हुई है। मेरी सरकार सहकारी संस्थाओं में सुदृढ़ीकरण के लिए भी चिन्तित है। इसलिए 9 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर को अनुदान के रूप में वहन कर रही है।

9. मुझे खुशी है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राज्य में एक नया कीर्तिमान बना है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 2045 करोड़ रू. की लागत से लगभग 35 लाख मीटरिक टन धान उपार्जन किया जा चुका है। इसके अलावा लिंकिंग के माध्यम से बैंकों की 269 करोड़ रू. से भी अधिक राशि की वसूली की जा चुकी है। साथ ही लिंकिंग से वसूली हेतु राज्य सरकार ने 15 फरवरी, 2006 तक धान उपार्जन करने का निर्णय लिया है।

10. मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। वर्ष 2005–2006 में लगभग 700 समन्वित मछली पालन इकाइयां स्थापित की गई हैं। राज्य गठन के समय मछली बीज का उत्पादन 25 करोड़ था, वह वर्श 2005–2006 में बढ़कर 50 करोड़ हो गया है। सवा लाख मीटरिक टन मछली उत्पादन के साथ अब छत्तीसगढ़ देश का आठवां प्रमुख राज्य बन गया है। मुछआरों का सरल ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 33 हजार मछुआरों को दुर्घटना बीमा योजना में शामिल किया गया है। मछली पालन से एक करोड़ मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

11. मेरी सरकार ने किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने में पशुपालन तथा डेयरी विकास को एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। व्यक्तिमूलक कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना एवं विशेष घटक योजना में 4 करोड़ रू. की धनराशि से 35 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। 10 करोड़ रू. की लागत से राष्ट्रीय गोवंशीय एवं भैंसवंशीय परियोजना के अंतर्गत स्थानीय कम उत्पादन की क्षमता के दुधारू पशुओं में नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान एवं प्रशिक्षण का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है।

12. एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के अंतर्गत 15 करोड़ रू. की लागत से रायगढ़, अंबिकापुर, कवर्धा, कोरिया एवं जशपुरनगर जिलों में कार्य शुरू किया गया है।

13. मेरी सरकार गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना भी 2 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ कर दी गई है इसका लाभ 11 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा एवं कोरिया के लोगों को मिलेगा। अन्य जिलों को भी इस योजना का लाभ दिलाने का आग्रह केन्द्र से किया गया है।

14. मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिन योजनाओं को प्रारम्भ करने की बात विगत वर्ष मैंने कही थी, उनमें काफी प्रगति भी हुई है। 'छत्तीसगढ़

गौरव' योजना के अंतर्गत 66 लाख रू. की लागत से 26 कार्य मंजूर हुए हैं। 'हमारा छत्तीसगढ़' योजना के तहत एक करोड़ रू. की लागत से 33 कार्य मंजूर हुए हैं। 'इन्द्रप्रस्थ' योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकासखंड मुख्यालयों में 25 लाख प्रति स्टेडियम की लागत से 69 मिनी स्टेडियम निर्मित किए जाएंगे। गली सीमेंटीकरण, सद्भावना भवन, केशवकुंज, मुक्तिधाम, गोठान निर्माण, कांजी हाऊस निर्माण तथा निर्मला घाट योजना के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर कार्य सम्पादित कराए जा रहे हैं। सिर्फ सीमेंट कांक्रीट सड़क योजना के अंतर्गत अब तक 142 करोड़ की लागत से 7426 गांवों में सीमेंट कांक्रीट रोड बनायी जा चुकी है।

15. पंचायतों को अधिकार सम्पन्न एवं कुशल बनाने के लिए मेरी सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं। पंचायतों के दायित्वों, अमले एवं वित्तीय व्यवस्था का मानचित्रण किया गया है। इनकी अपनी सूचना प्रणाली विकसित करने हेतु ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण एवं ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र विकसित करने की भी योजना है।

16. मेरी सरकार ने आम जनता को राजस्व संबंधी कार्यों में आने वाली परेशानियों को गंभीरता से समझा और उन्हें हल करने के नए–नए तरीके अपनाए। भुईंया कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर, जिला मुख्यालय स्तर, अनुभाग स्तर एवं राजस्व निरीक्षक मुख्यालय स्तर से कास्तकारों को कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराने की योजना के तहत इन समस्त स्थानों पर कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण करने एवं कम्प्यूटर तथा संबद्ध उपकरण की स्थापना का कार्य भी शुरू किया है। लगभग 3000 पटवारियों का कम्प्यूटर (ई–बस्ता) उपलब्ध कराने की योजना है। ऋण पुस्तिकाओं का कम्प्यूटरीकरण भी प्रस्तावित है, जिससे 43 लाख कास्तकारों को स्वच्छ एवं प्रामाणिक ऋण पुस्तिका की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा। इसी तरह जनसामान्य की सुविधा के लिये शेष 48 विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिया जाना है। इससे ग्रामीण जनता को अपने निवास स्थान से निकट शासकीय सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

17. 5 जिलों की 13 तहसीलों को अवर्षा की स्थिति को देखते हुये सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इन तहसीलों में राहत कार्य संचालन हेतु 6.50 करोड़ की धनराशि तथा 11,000 मी.टन चावल प्रदाय किया गया है। आपदाओं के निराकरण हेतु सभी जिला मुख्यालयों में आपदा केन्द्र (एमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर) निर्माण हेतु प्रत्येक जिले को 5 लाख रू. उपलब्ध कराए गए हैं। प्राकृतिक आपदा से आहत लोगों को राहत देने के लिए मेरी सरकार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि की गई है।

18. मेरी सरकार न वनवासियों–अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति के लोगों की समस्याओं को निकट से समझने और उनका हल करने के लिए समन्वित प्रशासनिक पहल की रणनीति अपनाई है। बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के माध्यम से न सिर्फ एक अरब रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए

गए, बल्कि इन प्राधिकरणों का कार्यक्षेत्र भी बढ़ाया गया। विभिन्न विभागों की प्रचलित योजनाओं को तेजी से पूरा करने के अलावा विशिष्ट जरूरतों की पूर्ति में यह व्यवस्था काफी सफल रही है। इन वर्गों के सामुदायिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं।

19. प्राथमिक कक्षा की तीन लाख कन्याओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया गया। माध्यमिक स्तर की करीब 25 हजार छात्राओं को निःशुल्क सायकिल दी जा रही है। हाईस्कूल के करीब 68 हजार छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई है। 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं में मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटर प्रदाय की योजना है।

20. 228 ग्रामीण आदिवासी प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य एवं राज्य के बाहर प्रतिष्ठित शासकीय निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया हे। आदर्श शाला पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी 16 हजार बच्चों को छात्रवृत्ति के अतिरिक्त विशेष पोषण हेतु 'भोजन सहाय योजना' का लाभ दिया जा रहा है। छात्रावास एवं आश्रमों के विद्यार्थियों हेतु विकासखंड स्तर पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना लागू की गई है।

21. 100 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जा रहा हैं। छात्रावास एवं आश्रमों में आवासीय सुविधा बढ़ाने हेतु 1960 सीटों की वृद्धि की जा रही है। 8 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिनमें प्रति विद्यालय 420 विद्यार्थी आवासीय सुविधा के साथ अध्ययन कर सकेंगे। आगामी वर्ष 2006–2007 में 118 नवीन प्री–मैट्रिक छात्रावास, 25 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 130 आश्रम खोले जाएंगे। 48 नवीन षैक्षणिक संस्थाओं के निर्माण हेतु 7 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। 47 नए छात्रावास एवं आश्रम भी खोले जाएंगे।

22. छात्रावास एवं आश्रमों में अध्ययनरत 60 हजार विद्यार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के विकास हेतु 18 हजार परिवारों को 'जनश्री बीमा' का सुरक्षा कवच एवं 550 परिवारों को आवास प्रदान किए जाएंगे। ग्रामोत्थान योजनान्तर्गत अनुसूचित बहुल 315 ग्रामों में प्रथम चरण में मंगल भवनों का निर्माण किया जाएगा।

23. मेरी सरकार ने वन और जीवन के बीच संबंध मजबूत करते हुए विकास का रास्ता बनाया है। संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से 32 वन मंडलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों के विकास में गति लाई गई है। करीब डेढ़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अंतः स्थलीय संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। लघु वनोपजों और वनौषधियों के प्रसंस्करण हेतु 221 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। 39 वन औषधालय स्थापित किए गए है।

24. काष्ठ एवं बांस के विदोहन, परिवहन, निर्वर्तन आदि कार्यों में 35 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया। सालबीज संग्रहण के बोनस के रूप में 8 करोड़ रू. का अतिरिक्त प्रावधान किया है। वर्ष 2005 में 9 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण हुआ। इस वर्ष करीब 15 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हुआ तथा संग्राहकों को लगभग 67 करोड़ रू. पारिश्रमिक वितरित किया गया। प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार को एक–एक जोड़ी चरण पादुका प्रदान करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। कुल 12 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों को मार्च 2006 तक चरण पादुका वितरण का कार्य कर लिया जाएगा।

25. प्रदेश में इमली, माहुपत्ता, शहद और वनौषधि के प्रसंस्करण एवं लाख पालन द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय उपलब्ध कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वनोपज आधारित रोजगारमूलक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 21 करोड़ रू. लागत की एक त्रिवर्षीय परियोजना यूरोपियन कमीशन द्वारा मंजूर की गई है।

26. सभी 425 वनग्रामों के विकास के लिए केन्द्र से 56 करोड़ रू. की तीन वर्षीय 'एकीकृत वनग्राम विकास योजना' की स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्वयन किया जा रहा है। वनांचलों में बसे वनग्रामों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की दौड़ में शामिल किया जाएगा।

27. रायपुर स्थित नंदनवन और बिलासपुर स्थित कानन पेंडारी को आदर्श चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं अचानकमार, उदंति, सीतानदी अभ्यारण्यों को 'प्रोजेक्टर टाइगर' योजना में शामिल कराया जा रहा है। जैव विविधता के संरक्षण हेतु अचानकमार–अमरकंटक अंतरराज्यीय बायोस्फीयर रिजर्व का गठन भी किया गया है।

28. मेरी सरकार ने महिलाओं को सामाजिक रूप से अधिकार सम्पन्न तथा आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। गरीब महिलाओं को टोनही(डायन) के अंधविश्वास से होने वाले उत्पीड़न की घटनाओं से बचाने के लिए सख्त कानून बनाकर लागू किया गया है। बाल विवाह तथा दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के निदान के लिए सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रति कन्या 5 हजार रू. की राशि स्वीकृत है। 9 हजार नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है, जिससे 10 लाख अतिरिक्त हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। महिलाओं के स्व–सहायता समूहों के गठन को बढ़ावा देते हुए अब तक 72 हजार समूहों का गठन किया जा चुका है जिससे लगभग 9 लाख महिलाएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं।

29. समाज के निराश्रित, निर्धन एवं उपेक्षित संवर्गों के लिए उनकी अधिकारिता विकसित करने व सम्मानपूर्वक जीवन–यापन करने हेतु सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सुखद सहारा योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में 4 लाख से अधिक

निराश्रित लाभान्वित हो रहे हैं तथा सुखद सहारा योजना का लाभ 13,200 विधवा–परित्यक्त महिलाएं प्राप्त कर रही हैं।

30. मेरी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को काफी गंभीरता से लिया है। इसके लिये नई सोच और साहस से काम किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन दुकानें निजी हाथों से वापस लेकर सहकारी संस्थाओं को देने का निर्णय सफल रहा। 2872 दुकानें निजी हाथों से वापस ली गई। 890 दुकानें लैम्प्स को, 3748 दुकानें सहकारी समितियों को, 3513 दुकानें पंचायतों को 1713 दुकानें स्व–सहायता समूहों को और 249 दुकानें वन सुरक्षा समितियों को दी गई है। इतना ही नहीं बल्कि 75 हजार रू. प्रति दुकान के मान से 40 करोड़ रू. की कार्यशील पूंजी भी प्रदान की गई। बी.पी.एल. योजना के तहत खाद्यान्न का उठाव 97 प्रतिशत से अधिक हो गया है, जो कि विगत वर्षों और राष्ट्रीय औसत 75 प्रतिशत से बहुत अधिक है। इस तरह अब 23 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने लगा है।

31. छत्तीसगढ़ अमृत नमक योजना में उठाव विगत वर्श की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक रहा। अब गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को 4 रू. प्रतिकिलो की दर से आयोडाइज्ड महामाया नमक का प्रदाय शुरू किया गया है। अन्नपूर्णा दाल–भात केन्द्रों से लगभग 30 हजार लोग प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। 11 विकासखण्डों में शुरू की गई जन केरोसिन परियोजना के अपेक्षित परिणाम मिले हैं। यह गर्व का विषय है कि खाद्य सुरक्षा कोष गठित करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है। सरकार की यह कोशिश है कि उचित मूल्य की दुकानें लोगों के घरों तक पहुंचें और किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को भूखा न रहना पड़े।

32. मेरी सरकार ने शहरों में सुनियोजित बसाहट के साथ नागरिक सुविधाएं और पर्यावरण की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए शहरी पुनर्सर्जना हेतु नगर निवेश के क्षेत्र में दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन योजनाएं बनाई जा रही हैं। जिनके आधार पर शहरों को योजनाबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। गोकुलनगर, ट्रांसपोर्टनगर, ज्ञानस्थली, सरोवर–धरोहर जैसी योजनाएं मूर्तरूप ले रही हैं। 65 नगरीय निकायों में 16 करोड़ रू. की लागत से नवीन बस स्टैंड–सह–व्यावसायिक परिसर का निर्माण किया जाएगा। सभी नगरों में 17 करोड़ रू. की लागत से 200 सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। 10 करोड़ रू. की लागत से 110 निकायों में 'मुक्तिधाम' निर्मित किए जाएंगे। नगरीय निकायों के बेहतर प्रबंधन हेतु जी.आई.एस.(ग्लोबल इमेज सिस्टम) के तहत बड़े शहरों का नक्शा बनाया जा रहा है, जिससे निकायों को योजना बनाने तथा करों की वसूली में भी सुविधा होगी।

33. मेरी सरकार ने नगरीय विकास की योजनाओं में कमजोर तबकों को रोजगार के नए अवसर जुटाने एवं छोटे व्यवसासियों की सुविधा बढ़ाने के उपाय किए हैं। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत राज्य में 2500 गुमटियां बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 11 करोड़ रू. की लागत

से 8000 से अधिक दुकानें निर्माणाधीन हैं, इनमें से 750 तो सिर्फ महिलाओं के लिए पृथक बाजार के रूप से रहेंगी।

34. मेरी सरकार ने ऐसी राज्य आवास नीति बनाई है जिसमें गरीबों के लिए आवास निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। गृह निर्माण मण्डल के माध्यम से राज्य में करीब 750 करोड़ रू. की लागत से 19 हजार आवासीय भवनों के निर्माण प्रगति पर हैं। न्यून–निम्न आय वर्ग के लिए 60 हजार करोड़ रू. की लागत से डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना, मध्यम आय वर्ग के लिए 100 करोड़ रू. की लागत से कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 30 करोड़ रू. की लागत से अटल आवास योजना के अलावा मिश्रित आय वर्ग के लिए भी विभिन्न आवासीय भवनों का निर्माण कार्य जारी है।

35. मेरी सरकार ने स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार करने के लिए समयबद्ध रणनीति अपनाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत 'राज्य स्वास्थ्य मिशन' और 'जिला स्वास्थ्य मिशन' गठित कर दिए गए हैं। ग्राम पंचायतों की स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से समुदाय आधारित 'ग्राम स्वास्थ्य योजना' बनाई जा रही है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायत विभाग के मध्य समन्वय होगा। अस्पतालों को सुदृढ़ कर उन्हें समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए कारगर उपाय किये जा रहे हैं। शिशु मृत्यु दर एवं माता मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 'शिशु सुरक्षा कवच', 'जननी सुरक्षा योजना' एवं 'जीवनदीप अस्पताल सुधार योजना' प्रारंभ की जा रही है।

36. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर 2 चिकित्सकों की पदस्थापना करने का महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी निर्णय मेरी सरकार ने लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 449 चिकित्सकों की पदस्थापना की जा रही है। 874 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रदेश में 200 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा 16 विकासखण्ड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उन्नयन प्रस्तावित है। प्रथम संदर्भ इकाईयों (एफ.आर.यू.) की संख्या को दो गुना करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह अब 64 एफ.आर.यू. से 24 घंटे स्वास्थ्य तथा सुरक्षित प्रसव की सेवायें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यूरोपियन कमीशन के साथ 150 करोड़ रू. के साझेदारी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा चुका है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य अधोसंरचना की कमियों को दूर कर सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

37. मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से प्रदेश में कुष्ठ रोग की प्रभाव दर 6 से घट कर 2.4 हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य 'पोलियो एवं याज' उन्मूलन की दहलीज पर खड़ा है। मलेरिया उन्मूलन के लिये सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है तथा वर्तमान में प्रचलित 'एनुवल पेरासीटिक इंडेक्स' की दर को घटा कर 2 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सिकलसेल विकृति की चुनौती से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों

में 'सालुबिलिटी टेस्ट' की सुविधा उपलब्ध करायी गई है तथा जिला चिकित्सालयों में इलेक्ट्रोफोरोसिस जांच की व्यवस्था की गई है। सरगुजा एवं बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में प्रारंभ की गई चलित चिकित्सालय सेवायें काफी लोकप्रिय हो रही हैं।

38. मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए हैं। दाखिले के लिए व्यापक जनभागीदारी से चलाए गए अभियान से अप्रवेशी 2 लाख 11 हजार 32 बच्चों का शाला प्रवेश संभव हुआ। 31 हजार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति की गई है तथा शिक्षाकर्मियों के 8500 नए पद स्वीकृत किए गए। 489 आश्रितों को शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। संविदा शिक्षकों, गुरूजी आदि पदों को शिक्षाकर्मियों में परिवर्तित किया गया, जिससे स्कूलों में समान गुणवत्ता के शिक्षक हों।

39. एक वर्ष में 1000 नवीन प्राथमिक विद्यालय एवं 1800 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। 2200 नवीन प्राथमिक शाला भवन, 1000 नवीन उच्च प्राथमिक शाला भवन, 2000 कक्ष, 425 शौचालय एवं 500 पेयजल स्त्रोत स्वीकृत किए गए हैं। 900 संकुल केन्द्र भवन, 100 हाईस्कूल भवन एवं 66 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन भी स्वीकृत किए गए।

40. मेरी सरकार ने मध्यान्ह् भोजन योजना को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ बच्चों की सेहत के लिए भी नई योजना शुरू की है। शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों में 29 लाख बच्चों को प्रतिदिन गर्म मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। इसके लिए निःशुल्क चावल, 12500 स्कूलों में गैस कनेक्शन एवं गैस चूल्हे देने की व्यवस्था की गई हैं। 7000 किचन शेड स्वीकृत किए गए हैं। खाना पकाने के काम में महिला स्वसहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाई गई है। बच्चों को यथासंभव प्रतिदिन हरी सब्जी, फल, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियां तथा छह माह में एक बार विटामिन–ए एवं कृमिनाशक दवा भी देने के निर्देश हैं। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना भी प्रारंभ की गई हैं इसके तहत बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनके स्वास्थ्य की जानकारी भरी जाएगी। बीमार बच्चों का इलाज भी किया जाएगा।

41. शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें तथा अभ्यास पुस्तकें दी जा रही हैं। 50 स्कूलों में टच स्क्रीन कम्प्यूटरों से खेल–खेल में पढ़ाई के लिए 'एकलव्य कम्प्यूटर आधारित स्वास्थ्य केन्द्र' योजना शुरू की गई है।

42. शिक्षा के प्रति बालिकाओं को प्रेरित करने के लिए मेरी सरकार ने अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। प्राथमिक स्तर की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की करीब 8 लाख बालिकाओं को निःशुल्क सायकल दी जा रही हैं। हाईस्कूल की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें दी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना के अंतर्गत 1100 स्कूलों में एक लाख बालिकाओं को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा दी जा

रही हैं। 51 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। 99 विकासखंडों में 990 सहेली शाला भवन मंजूर किए गए।

43. अच्छे शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी, डॉ. बल्देव प्रसाद मिश्र, श्री गजानन माधव मुक्तिबोध एवं डॉ. मुकुटधर पाण्डेय के नाम पर राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रारम्भ किए हैं। शिक्षकों को राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त करने पर एक वेतन वृद्धि एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने पर दो वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है।

44. विगत वर्षों मैंने कहा था कि राज्य में तीन नए विश्वविद्यालय शुरू हो जाएंगे। मेरी सरकार ने उन तीन नए विश्वविद्यालयों के साथ जगदलपुर तथा सरगुजा में दो नए विश्वविद्यालय परिसर भी शुरू कर दिए हैं। सभी 16 जिलों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय खोले गए हैं तथा महिला महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। दूरस्थ अंचलों के विकासखण्ड मुख्यालयों में नवीन महाविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। 17 महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। 10 महाविद्यालयों को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा अन्य 24 महाविद्यालयों को भी विकसित किया जाएगा। सभी महाविद्यालयों में भवनों के निर्माण, मरम्मत, प्रयोगशाला, वाचनालय जैसी आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं।

45. मेरी सरकार ने राज्य में तकनीकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं जुटाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रायपुर के इंजीनियरिंग महाविद्यालय को एनआईटी का दर्जा मिलने से राज्य गौरव बढ़ा है। जगदलपुर ने नया चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में एक नया इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा जशपुर में नया पॉलीटेक्निक प्रारम्भ किया जाएगा। 4 अग्रणी महाविद्यालयों में ई–क्लास रूम विकसित कर इन्हें आई.आई.टी. कानपुर से जोड़ा जाना है। एक वर्ष में 7 नए आई.टी.आई. खोले गए हैं। 4 आई.टी.आई. को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और उसकी संपदा एवं शोधपूर्ण विवरण पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी की स्थापना की गई है जिसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

46. मेरी सरकार ने पत्रकारों व उनके परिवारजनों के सुख–दुख का भागी होते हुए पत्रकार कल्याण कोष से 26 पत्रकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। प्रदेश के पत्रकारों को आधुनिक संचार प्रणाली का पूरा लाभ देने के उद्देश्य से जनसंपर्क संचालनालय में आधुनिक मीडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी।

47. मेरी सरकार ने बिजली को आम आदमी के विकास और जीवन स्तर उन्नयन का साधन बनाने की दिशा में काम किया है। सभी को निरंतर और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदाय के लिए पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन पर 1, 014 करोड़ रू. का निवेश किया गया है। इससे काफी हद तक लो–वोल्टेज की समस्या से निजात मिली है। 94 प्रतिशत आबाद ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष 1191 ग्रामों में से

1,055 ग्राम वनबाधित हैं, इनमें से 350 का विद्युतीकरण आगामी एक वर्ष में गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से किया जाएगा।

48. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'अटल ज्योति योजना' लागू की जा रही है। इसके तहत विद्युत पम्पों की आपूर्ति को रहवासी क्षेत्रों की आपूर्ति से पृथक किया जा रहा है। इससे विद्युत संकट की स्थिति में रहवासी क्षेत्रों को निरंतर विद्युत प्रदाय किया जा सकेगा। 5 वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी आवासों में विद्युत उपलब्ध कराने की योजना भी प्रारम्भ कर दी गई है। 3 वर्षो में विद्युत पम्प के एक लाख नए कनेक्शन देने के संकल्प के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष अब तक 22 हजार नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

49. मेरी सरकार ने नए बिजलीघरों की स्थापना में तेजी लाई है। 500 मेगावाट की कोरबा (पूर्व) परियोजना निर्माणाधीन है। कोरबा (पश्चिम) में 250 से 300 मेगावाट की दो इकाइयों की स्थापना तथा इफ्को के साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का संयुक्त उपक्रम बनाकर प्रेमनगर जिला सरगुजा में एक हजार मेगावाट का ताप विद्युत गृह लगाने की योजना प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त 1320 मेगावाट क्षमता की भैयाथान ताप विद्युत परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से 500 मेगावाट की बोधघाट जल विद्युत परियोजना पर भी कार्य प्रारम्भ करने की योजना है। निजी क्षेत्र में जिन्दल पावर लिमिटेड द्वारा रायगढ़ में 1000 मेगावाट क्षमता का एवं लेंको अमरकंटक द्वारा पथाडी (कोरबा) में ताप बिजलीघर निर्माणाधीन है।

50. मेरी सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश के प्रथम बायोडीजल राज्य के रूप में प्रसिद्धि दिलाने में सफलता पाई है। रतनजोत के व्यावसायिक उत्पादन से लेकर बायोडीजल उत्पादन और बिक्री तक की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होने की संभावनाएं हैं। पड़त भूमि पर रतनजोत के 6 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। अब 16 करोड़ पौधे रोपित करने की योजना है। 3 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता का बायोडीजल प्लांट शुरू हो गया है।

51. राज्य के सिंचाई प्रतिशत को राष्ट्रीय औसत 38 प्रतिशत के समकक्ष लाना पहली चुनौती है। वर्तमान में सिंचित रकबा 16 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जो निरे बोये गए क्षेत्र का लगभग 33 प्रतिशत एवं कुल बोए गए क्षेत्र का 28 प्रतिशत है। मेरी सरकार ने अपूर्ण योजनाओं को कम समयावधि में पूर्ण करने को प्राथमिकता दी है। पिछले दो वर्षो में 137 योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा एक लाख 73 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण किया गया।

52. वर्तमान में 5 वृहद, 9 मध्यम एवं 376 लघु योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जिन्हें 4 वर्षो में पूरा कर करीब 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। राजीव व्यपवर्तन, हसदेव बांगो, अपर जोंक, महानदी परियोजना समूह, सोंढूर, मोंगरा आदि परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। वर्षो से लंबित घुमरिया, सूखानाला, कर्रानाला परियोजनाओं को प्रारम्भ किया गया।

53. मेरी सरकार ने नदियों पर 1650 करोड़ रू. की लागत से 595 एनीकट बनाने की योजना शुरू की है। एनीकट से सिंचाई के अतिरिक्त निस्तार, पेयजल,कृषि, उद्योगों आदि प्रयोजनों के लिए जल आपूर्ति की जा सकेगी। एनीकट निर्माण से 85 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। वर्तमान में 37 एनीकट बनाए जा चुके हैं तथा शिवनाथ, खारून, सोन, गेज, सूखानाला, इन्द्रावती, डंकिनी, दूध आदि नदियों पर 59 एनीकट निर्माणाधीन हैं। ए.डी.बी. की सहायता से 300 करोड़ रू. की लागत से 'छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास परियोजना' के तहत पुरानी 200 लघु एवं 20 मध्यम परियोजनाओं के पुनरूद्धार एवं उन्नयन का कार्य किया जाएगा।

54. मेरी सरकार ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के अलावा स्वच्छ परिवेश एवं स्वच्छ पर्यावरण निर्माण का जरिया भी माना है। नई 11,803 सर्वेक्षित बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य मार्च 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण जल प्रदाय की 839 योजनायें पूर्ण कर संधारण हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी है। 93 आंशिकपूर्ण योजनाओं से भी ग्रामवासियों को पेयजल प्रदाय शुरू कर दिया गया है।

55. स्वजलधारा योजना के अंतर्गत राज्य के 14 जिलों में 6 करोड़ रू. की लागत की 312 योजनाएं स्वीकृत की गई है। इनके अमल एवं अनुश्रवण हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं ग्राम स्वच्छता समितियों का गठन भी किया गया है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत 10 जिलों में 145 करोड़ रू. लागत की योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 5 जिले के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर केन्द्र शासन को भेजी जा चुकी है। पारिवारिक शौचालय निर्माण की योजना अभी हाल में स्वीकृत की गई है, जिनका कार्य शीघ्र प्रारंभ कर आगामी तीन वर्षो में 10 लाख शौचालय निर्मित किये जायेंगे। जिनमें से 1 लाख पारिवारिक शौचालय बीपीएल परिवारों व अजा–अजजा परिवारों के लिए इसी वर्ष बनाये जायेंगे।

56. स्पॉट सोर्स की 1357 योजनाओं में से 463 योजनाओं को पूर्ण कर संबंधित ग्राम पंचायतों को संधारण हेतु सौंपा गया है, 187 अपूर्ण योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। एवं 707 योजनायें अभी हाल ही में स्वीकृत की गई हैं।

57. शहरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना मद में स्वीकृत 14 योजनाओं में से 6 योजनाएं पूर्ण की गई एवं शेष 8 योजनाएं प्रगतिरत् हैं। केन्द्रीय गतिवर्धित नगरीय जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले नगरों की 40 योजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 18 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं, 22 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। भू–जल सवंर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य की 12 करोड़ रू. लागत की 40 योजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बिलासपुर जिले की 4 योजनाएं स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई हैं।

58. मेरी सरकार ने अच्छी सड़कों को विकास की रफ्तार बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया माना है। चालू वित्तीय वर्ष में 3661 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, गिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण कार्य किए गए हैं। 38 पुलों का निर्माण पूरा हुआ और 152 के कार्य प्रगति पर हैं। छह कारीडोर सड़कों का निर्माण 860 किलोमीटर तक पूर्ण किया गया है।

59. नाबार्ड ऋण से 599 करोड़ रू. की लागत से 280 सड़कें तथा 301 पुल निर्माण की मंजूरी मिली, जिसमें से 441 करोड़ रू. की लागत से 144 सड़कों तथा 220 पुलों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इस वर्ष 98 करोड़ रू. की लागत से 64 सड़कों, 36 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया। केन्द्रीय सड़क निधि से 25 सड़कों के लिए 125 करोड़ रू. की मंजूरी मिली तथा 80 करोड़ रू. की लागत से 15 सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 10 करोड़ रू. की लागत से दो अंतर्राज्यीय सड़कें बनाई गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत 52 करोड़ रू. की लागत से 57 कार्यों की मंजूरी मिली। इनमें से 36 करोड़ रू. की लागत से 23 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। ए.डी.बी. से 1600 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन हेतु 1286 करोड़ रू. की मंजूरी मिली है, जिसके प्रथम चरण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा।

60. सुगम एवं बाधारहित यातायात के लिए कोरबा, भाटापारा, दुर्ग, उसलापुर (बिलासपुर) दाधापरा (बिलासपुर) रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण का कार्य प्रगति पर है एवं शेष 5 कार्य प्रारम्भ करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन कार्यो हेतु वर्ष 2005–2006 में 12 करोड़ रू. के बजट प्रावधान के विरूद्ध 10 करोड़ रू. का व्यय किया गया है। 10 शहरों में 19 बायपास मार्गों के निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है। रायपुर से दुर्ग फोरलेन का कार्य तेजी से जारी है। रायपुर–बिलासपुर, रायपुर से धमतरी, रायपुर से आरंग को फोरलेन में परिवर्तित करने की योजना है। मेरी सरकार ने लोक निर्माण, जल संसाधन जैसे विभागों में निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए 20 लाख रू. से अधिक के कार्यों में ई–टेंडरिंग प्रणाली और बेरोजगार स्नातक इंजीनियरों को 10 लाख रू. तक के कार्य बिना निविदा के देने की योजना भी लागू की है।

61. मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लाभ उठाने में सराहनीय तत्परता दिखाई। इस योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी दो राज्यों में शामिल है। राज्य को इस योजना में अभी तक 2100 सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिली है, जिसकी लम्बाई 11 हजार किलोमीटर तथा लागत 2273 करोड़ रू. है। इनमें से 800 करोड़ रू. की लागत से 4000 किलोमीटर लम्बी 600 सड़कों एवं 6000 पुल–पुलियों का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना के पांचवें चरण एवं ए.डी.बी. द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत 992 सड़कों हेतु 1000 करोड़ रू. की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

62. मेरी सरकार की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के वर्तमान दौर में दीर्घावधि में हमारे उद्योगों का लाभकारी स्थिति में बने रहना, उन्हें कच्चे माल की वाजिब कीमत पर सुनिश्चित आपूर्ति पर निर्भर करेगा। इसलिए प्रदेश में उपलब्ध खनिजों की खनि रियायतें प्रदेश के उद्योगों को उपलब्ध कराने हेतु विशेष

प्रयास किए जा रहे हैं। विगत एक वर्ष के दौरान 18 इकाइयों को लौह अयस्क की खनि रियायतें स्वीकृत या अनुमोदित की गई और 14 इकाईयों को केन्द्र सरकार से केप्टिव कोयला ब्लाकों का आवंटन कराया गया। राज्य के खनिजों के दोहन से राज्य सरकार को अधिक से अधिक राजस्व मिले, इस दृष्टि से राज्य खनिज विकास निगम को पूर्व से आबंटित तारा कोयला ब्लाक के अतिरिक्त कोयले के चार और ब्लाकों के आबंटन के लिए केन्द्र सरकार को अनुशंसाएं भेजी गयी हैं। निगम को बाक्साइट, कोरंडम तथा टिन की 17 खनि रियायतें स्वीकृत करने के निर्णय लिए गए हैं। बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन के लिए एनएमडीसी के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने का निर्णय लिया गया है।

63. प्रसन्नता का विषय है कि विगत वर्ष के दौरान हीरा, सोना आदि बहुमूल्य खनिजों की खोज के लिए 15258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में टोही अनुज्ञा पत्रों के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किए गए और चूना पत्थर के 275 लाख टन तथा बाक्साइट के लाख टन नये भंडार चिन्हित किए गए हैं।

64. मेरी सरकार ने औद्योगीकीकरण से रोजगार के नए अवसर सृजित करने एवं अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जो औद्योगिक नीति 2004–09 लागू की थी, वह कारगर साबित हुई है। उद्योगों में पूंजी निवेश के लिए हुए करारों और वास्तविक निवेश के मामले में विगत वर्ष छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों में अग्रणी भी रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बस्तर में औद्योगिक क्रांति का शिलान्यास है। हमारी कामना है कि देश के विख्यात औद्योगिक प्रतिष्ठान टाटा स्टील तथा एस्सार स्टील लिमिटेड के साथ बस्तर में 15 हजार करोड़ रू. से अधिक निवेश के जो करार हुए हैं, वे जल्दी ही पूरे हों।

65. औद्योगिक विकास को गति देने हेतु मेरी सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव तथा रायगढ़ जिलों में 4 वृहद औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार राज्य में समूह आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग पार्क, हर्बल एवं मेडीसिनल पार्क, जेम एवं ज्वेलरी पार्क, बायो एवं आई.टी.पार्क, मेटल पार्क एवं अपेरल पार्क की स्थापना हेतु परियोजना सलाहकारों के माध्यम से निवेशकों के आमंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

66. वर्ष 2005–2006 के नौ महीनों में राज्य में 38 मध्यम–वृहद उद्योग एवं 425 लघु उद्योग स्थापित होकर उत्पादन प्रारंभ कर चुके हैं। जिनमें 696 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। साथ ही 25 मध्यम–वृहद उद्योग एवं 10 मेगा परियोजना निर्माणाधीन हैं। राज्य में स्पंज आयरन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 50 लाख टन तक पहुंच चुकी है एवं इस उद्योग में लगभग 2000 करोड़ का निवेश हुआ है।

67. मेरी सरकार ने ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर, गांव–गांव में परम्परागत रोजगार के अवसरों में नया निखार लाने के प्रयास किए हैं। पालित डाबाटसर ककून उत्पादन में नई ऊंचाईयों पर पहुंचे हैं। विशेष टसर

विकास परियोजना के तहत 250 हेक्टेयर में टसर खाद्य पौधरोपण हेतु 14 करोड़ रू. की योजना केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है। राज्य आयोजना मद से 22 करोड़ रू. की लागत से एकीकृत टसर विकास परियोजना प्रस्तावित है। 8 जिलों के प्राकृतिक वनखण्डों में नैसर्गिक कोसा प्रगुणन एवं संग्रहण कैम्प स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में प्रथम बार प्रायोगिक रूप से जशपुर एवं सरगुजा जिले में अरण्डी से ईरी रेशम का उत्पादन प्रारम्भ किया गया। विभिन्न रेशम योजनाओं से 81 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

68. मेरी सरकार ने हाथकरघा उद्योग में बुनकरों एवं सम्बद्ध 42 हजार से अधिक लोगों को दीनदयाल हाथकरधा प्रोत्साहन योजना, हेल्थ पैकेज योजना, वेलफेयर योजना, बाजार अध्ययन, अनुसंधान एवं विकास योजनाएं तथा प्रोजेक्ट पैकेज योजना, रिवाल्विंग फण्ड योजना, कर्मशाला जीर्णोद्धार योजना तथा कम्प्यूटर एडेड डिजाइन केन्द्र आदि से जोड़ा है। 11 करोड़ रू. के वस्त्र प्रदाय आदेश विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त हुए हैं, जो कि विगत वर्षों की तुलना में अधिक है। वर्ष 2006–07 में हाथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण, डिजाइन विकास, टेक्नालॉजी हस्तांतरण, क्वालिटी कंट्रोल एवं निर्यात योग्य हाथकरघा वस्त्रों के उत्पादन विकास का लक्ष्य है।

69. मेरी सरकार खादी का काम करने वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिए उत्पादन अनुदान एवं कत्तिन अनुदान योजना लागू कर रही है, जिसमें 5000 व्यक्तियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत 188 ग्रामोद्योग इकाइयों को 18 करोड़ रू. की आर्थिक सहायता विभिन्न बैंकों के माध्यम से स्वीकृत की गई है, जिसमें 6000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग की 900 इकाइयों को करीब एक करोड़ रू. अनुदान की आर्थिक सहायता देकर 2500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हस्तशिल्प के 7000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। विपणन हेतु रायपुर में 'छत्तीसगढ़ हाट' की स्थापना की जा रही है। फ्यूजन आर्ट स्कूल, हस्तशिल्प प्रशिक्षण केन्द्र कार्यान्वित करने की योजना है।

70. मेरी सरकार श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिये लगातार कार्य कर रही है। राज्य में पहली बार 17 सितम्बर को विश्वकर्मा जयंती को 'छत्तीसगढ़ श्रम दिवस' के रूप में मनाए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। जांजगीर–चांपा में नये श्रम पदाधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई है। बिलासपुर श्रम कार्यालय का सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में उन्नयन किया गया है। बीड़ी श्रमिकों के लिए बिलासपुर जिले में 284 आवासों का निर्माण पूर्ण कर आबंटित किया जा चुका है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में 200 आवासों में से 84 बीड़ी श्रमिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के अंतर्गत भिलाई तथा कोरबा में नए अस्पताल खोले जाएंगे। रायपुर में एक सुसज्जित डायग्नोस्टिक केन्द्र खोला जाएगा।

71. आम जनता को परिवहन संबंधी कार्यों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 8 जिलों में नए परिवहन कार्यालय प्रारम्भ किए गए हैं। पहली बार परिवहन विभाग ने राजस्व अर्जन लक्ष्य से अधिक कर 107 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की है।

72. मेरी सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व के बहुआयामी पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं। 16 जिलों में 21 हाइवे मोटल का निर्माण कराया जा रहा है। 21 राज्य स्तरीय गाइड एवं 20 क्षेत्रीय गाईडों का चयन कर ट्रेनिंग हेतु भेजा गया। राज्य के भीतर एवं अन्य प्रदेशों में पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये गये। रायपुर में होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है।

73. विशिष्ट पर्यटन स्थलों जैसे– सिरपुर, मैनपाट, बस्तर के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है। इको टूरिज्म सहित चिन्हांकित स्थलों के लिये अच्छी अधोसंरचना का विकास प्राथमिकता से किया जा रहा है। आशा है कि आगामी 2 वर्षों में करीब 100 करोड़ रूपये की पूंजी निवेश पर्यटन के क्षेत्र में होगा।

74. अपने राज्य की वैभवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिये मेरी सरकार ने जनआकांक्षाओं के अनुरूप अभिनव प्रयास किये हैं। सिरपुर में उत्खनन से राज्य के गौरवमयी इतिहास के अनेक प्रमाण अर्जित हुए हैं। इस कार्य को और भी आगे बढ़ाया जायेगा। कोशिश यह होगी कि सिरपुर का नाम विश्व हेरिटेज के रूप के दर्ज हो। अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर तथा रायपुर में पुरातत्वीय संग्रहालय के विकास के साथ ही इनको सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों में मेलों एवं प्राचीन आयोजनों को पुनर्जीवित करने में अच्छी सफलता मिली है। इस कड़ी में राजिम को प्रयागराज कुंभ की प्रतिष्ठा दिलाने की तैयारी जोरों पर है।

75. मेरी सरकार ने न्यायिक संस्थाओं का मान बढ़ाने के साथ ही जन उपयोगी बनाने की दिशा में हर संभव सहयोग दिया है। राज्य बनने के बाद 4 राजस्व जिलों को सिविल जिला घोषित किया जा चुका है तथा शेष 5 राजस्व जिलों को भी सिविल जिला बनाने की कार्रवाई जारी है। राज्य स्तर पर माध्यस्थम अधिकरण का गठन किया गया है। पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए 11 परिवार न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रायपुर, अंबिकापुर तथा जगदलपुर में स्थायी लोक अदालत स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। गांवों में सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालयों का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। वहीं निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय सीमा 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रू. कर दी गई है। राज्य के 11 सिविल जिलों में लीगल एंड आनलाईन शुभारम्भ किया गया है, जिससे दूरस्थ निवास करने वालों को उनके अधिकार की जानकारी दूरभाष से प्राप्त हो सके।

76. ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र ने राज्यों के लिए मध्यावधि राजकोषीय सुधार योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ राज्य ने इस योजना में निश्चित अनुपात में राजस्व घाटा कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए 5 वर्षों के लिए निर्धारित सम्पूर्ण राशि 113.66 करोड़ रू. प्राप्त की है। बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्र की राज्यों के लिए शुरू किए ऋण समेकन तथा राहत योजना से छत्तीसगढ़ को वर्ष 2005–2006 में 85 करोड़ रू. राशि प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण (ई–कोष प्रोजेक्ट) को राजस्व सेवाओं में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ मानते हुए प्रथम पुरस्कार oracle "e-governance excellence" अवार्ड प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के आकलन में छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इस वर्ष वाणिज्यिक कर राजस्व संग्रहण में 26.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 456 करोड़ रू. की आबकारी आय हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 30.42 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार पंजीयन विभाग द्वारा दिसम्बर तक 203 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 29.19 प्रतिशत अधिक है।

77. मेरी सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार के कार्यों में पारदर्शिता और जनसुविधाएं बढ़ाने की पहल की है। भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण कर नक्शा, खसरा एवं बी–1 की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां दी जा रही हैं। सभी 146 विकासखंड वी–सेट से जोड़े गए हैं। 10 विकासखंड में सरपंचों को सिम्प्यूटर वितरण किया जा रहा है। ई–टेंडरिंग योजना से विभिन्न विभागों में निर्माण कार्यो की निविदा इंटरनेट के माध्यम से जारी की जाती है। ई–प्रोक्योरमेंट योजना के तहत सरकारी विभागों में सामग्री का क्रय भी इंटरनेट के माध्यम से किया जाने लगा है। ई– गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

78. राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरी सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु विगत दो वर्षों में 55 करोड़ रू. की मंजूरी दी है, जिससे अधोसंरचना तथा कार्यदक्षता में वृद्धि की सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की छह बटालियन, छत्तीसगढ़ विशेष सशस्त बल की सात बटालियन, नागालैंड पुलिस की एक बटालियन एवं जिला पुलिस बल तैनात किया गया है। राज्य के पुलिस कर्मियों को गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कांकेर में कॉलेज की स्थापना की गई है। दक्षिण बस्तर में सलवा जुडूम के भागीदारों की सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं। नक्सलवादी हिंसा की समस्या की व्यापकता को देखते हुए वनवासियों के संघर्ष की क्षमता और साहस की सराहना की जानी चाहिए। नक्सलवाद की चुनौती से निपटने के लिए वनवासियों के स्वस्फूर्त आंदोलन को राज्य में जिस तरह सभी दलों और आप लोगों का समर्थन मिल रहा है वह भी सराहनीय है। मेरी कामना है कि सलवा जुडूम सफल हो और नक्सलवादी हिंसा पूरी तरह समाप्त हो जाए।

79. मेरी सरकार ने अंत्योदय के लिए नए उपायों के साथ ही विभिन्न्न क्षेत्रों में विकास के शिखरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया है। अनेक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की पहचान भी बनने लगी है। अभी जो सफलताएं और उपलब्धियां दिखाई पड़ रही हैं, उसे मंजिल नहीं माना जाना चाहिए। मैं आप सब जनता के नुमाइंदों से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र पर अपना विश्वास अटल रखें। लोकतांत्रिक तौर–तरीकों से ही कार्य करने पर हम व्यापक पारदर्शिता के साथ कार्य कर सकते है और आम जनता का विश्वास जीत सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधन विकास की अपार संभावनाएं और अवसर उपलब्ध कराते हैं। उनका उपयोग व्यापक जनहित में करते हुए सबके विकास और जीवन स्तर में वृद्धि का लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए। ऐसे प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ को देश का अव्वल राज्य बनाया जा सकेगा।

जय हिन्द । जय छत्तीसगढ़ ।